हादसा | शादी समारोह से बाइक पर लौट रहें थे तीन युवक, दो अन्य घायल

अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत

अनूपपुर, नवभारत 14 फरवरी।। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर शनिवार को आमाडांड मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 25 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। घटना में बाइक सवार दो अन्य युवक घायल हो गए।

स्थानीय लोगों की सूचना पर 100 डायल और रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी सुमित कौशिक ने बताया कि मृतक की पहचान ग्राम फुलकोना निवासी महावीर चौधरी के 25 वर्षीय पुत्र दीपक चौधरी के रूप में हुई है। घायलों में रिंकू चौधरी और एक अन्य युवक शामिल हैं। दीपक चौधरी अपने पिता महावीर चौधरी और कुछ दोस्तों के साथ छत्तीसगढ़ के ग्राम चलचली में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। समारोह के बाद दीपक और उनके दो साथी बाइक से अपने गांव फुलकोना लौट रहे थे, जबकि उनके पिता उनके साथ नहीं लौटे। आमाडांड मार्ग पर पहुंचते ही उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों बाइक सवार गिर गए। बाइक चला रहे दीपक चौधरी को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद अन्य दोनों घायल युवक बिना किसी को बताए अपने घर चले गए थे। पुलिस को आशंका है कि युवक शराब के नशे में हो सकते थे। पुलिस दोनों घायल युवकों से पूछताछ कर रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

एमबी पावर स्कूल अब डीएव्ही प्रबंधन के अधीन, 1 अप्रैल से होगा संचालन

अनूपपुर, नवभारत, 14 फरवरी। एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड द्वारा संचालित परियोजना टाउनशिप स्थित 10+2 सीबीएसई संबद्ध विद्यालय का संचालन एवं प्रबंधन अब देश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था डीएव्ही कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजमेंट सोसायटी के अधीन किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। कंपनी प्रबंधन ने यह निर्णय विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, अधोसंरचना तथा प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया है। कंपनी प्रबंधन ने बताया कि इस विद्यालय की स्थापना कर्मचारियों के बच्चों, परियोजना प्रभावित परिवारों तथा आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान वर्षों से क्षेत्र में शिक्षा और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। डीएव्हीन प्रबंधन वर्तमान में देशभर में 1000 से अधिक शिक्षण संस्थानों का संचालन कर रहा है। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी 136 से अधिक विद्यालयों का सफल संचालन डीएव्ही0 द्वारा किया जा रहा है। बेहतर शैक्षणिक परिणाम, अनुशासित वातावरण, मूल्य-आधारित शिक्षा तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए डीएव्ही विद्यालयों की देशभर में पहचान है।एमबी पावर प्रबंधन के अनुसार विद्यालय को डीएव्हीा के पेशेवर प्रबंधन में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का उपयोग, खेल व सह-पाठयक्रम गतिविधियों का विस्तार तथा डिजिटल लर्निंग को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रबंधन परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुचारु रखा जाएगा, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह कदम विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और इससे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर और बेहतर होने की उम्मीद है।

नपा अध्यक्ष के कार्यों की चहुंओर प्रशंसा

कोतमा, नवभारत। राजनीति में अक्सर पद और प्रतिष्ठा व्यक्ति के व्यवहार को बदल देती है, लेकिन कोतमा नगर पालिका अध्यक्ष अजय सराफ ने अपनी सादगी और सुलभता से इस धारणा को बदल दिया है। आज नगर के हर कोने में, लोगों की जुबां पर उनके द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से ज्यादा उनकी 'सरलता' की चर्चा है। 'हां भैया, हो जाएगा' - जन-जन का भरोसा नगर में यह बात आम हो चुकी है कि यदि कोई अपनी समस्या लेकर अध्यक्ष के पास जाता है, तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता।

प्रमुख विकास कार्यों पर एक नज़र

पालिका बाजार (वार्ड नं. 3): हाल ही में वार्ड नंबर 3 स्थित अत्याधुनिक 'पालिका बाजार' का लोकार्पण हुआ है। यहाँ 18 नई दुकानें बनकर तैयार हैं, जिससे न केवल नगर का सौंदर्य बढ़ा है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों को अपना रोजगार बढ़ाने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा।

बस स्टैंड परिसर (वार्ड नं. 4): बस स्टैंड परिसर का कायाकल्प और निर्माण कार्य पूर्ण होने से यात्रियों और स्थानीय निवासियों को बड़ी सुविधा मिली है।

परशुराम भवन (वार्ड नं. 13): वार्ड 13 में भव्य मंगल भवन का निर्माण होने जा रहा है, जिसे 'परशुराम भवन' के नाम से जाना जाएगा। यह मांग लंबे समय से लंबित थी।ऑडिटोरियम (वार्ड नं. 1): सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए वार्ड नंबर 1 में एक विशाल ऑडिटोरियम जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है।

स्टेशन चौक कॉम्प्लेक्स: स्टेशन चौक के पास बन रहा व्यापारिक कॉम्प्लेक्स भी अब पूर्णता की ओर है। सड़कों का जाल: नगर के विभिन्न वार्डों में सीसी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे कीचड़ और खराब रास्तों से मुक्ति मिल रही है। नगरवासियों का कहना है कि अध्यक्ष न केवल सुनते हैं, बल्कि उसे धरातल पर उतारते भी हैं।

नाबालिग अपहृता को केरल से किया दस्तयाब

अनूपपुर, नवभारत, 14 फरवरी। थाना वेंकटनगर पुलिस ने 17 वर्षीय अपहृता नाबालिग किशोरी को केरल के इडुक्की जिले से सुरक्षित दस्तयाब कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार 4 जनवरी को ग्राम सिंघौरा निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 17 वर्ष 1 माह की नाबालिग नातनी के अचानक घर से लापता हो जाने की रिपोर्ट थाना जैतहरी अंतर्गत वेंकटनगर में दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस द्वारा धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी अमर वर्मा के नेतृत्व में गुमशुदा बालिका की खोज के लिए विशेष अभियान चलाया गया। वेंकटनगर पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सेल की मदद से अपहृता की लोकेशन ट्रेस की। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने किशोरी को 11 फरवरी को उड्डुमबनचोला, जिला इडुक्की (केरल) से सुरक्षित दस्तयाब कर लिया।

'अदृश्य विकास' का चमत्कार, कागजों पर ही उगा दिया 5 लाख का पार्क!

जमुना कोतमा नवभारत, 14 फरवरी। सरकारी तंत्र में 'ऊपर से खाऊ और नीचे से बाटू' का खेल तो पुराना है, लेकिन जनपद पंचायत अनूपपुर की ग्राम पंचायत रेउला में भ्रष्टाचार की जो नई इबारत लिखी गई है, उसने जिले के प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। यहाँ विकास की ऐसी 'जादुई छड़ी' चली है कि जमीन पर एक गड्ढा तक नहीं खोदा गया, लेकिन सरकारी तिजोरी से लाखों रुपये गायब हो गए। सचिव विमल साहू की जादुई कलम ने फाइलों में एक ऐसा हरा-भरा पार्क खड़ा कर दिया है, जिसे रेउला की जनता आज भी अपनी आँखों से देखने के लिए तरस रही है। यह मामला सीधे तौर पर जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने और सरकारी योजनाओं का मजाक उड़ाने का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया है। अगर इस पूरे घोटाले की गहराई में जाएँ तो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक रेउला में 'ग्रामीण पार्क' निर्माण के लिए 4,79,000 की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई थी। पंचायत राज के कड़े नियम और निर्देश स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी निर्माण कार्य का भुगतान उसकी भौतिक प्रगति यानी जमीन पर हुए काम को देखकर ही किस्तों में किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो सचिव विमल साहू की 'सेटिंग' और रसूख के आगे नियम बौने साबित हो गए। धरातल पर काम के नाम पर एक पत्थर भी नहीं हिला और न ही सुंदरीकरण की कोई शुरुआत हुई, मगर सचिव महोदय की प्रशासनिक चतुराई देखिए कि उन्होंने लगभग ?4,00,000 की राशि का आहरण सफलतापूर्वक कर लिया। बिना काम के इतनी बड़ी रकम की निकासी करना न केवल वित्तीय अनियमितता है, बल्कि एक गहरी आपराधिक साजिश की ओर इशारा करता है।इस पूरे खेल में सबसे संदिग्ध और रहस्यमयी भूमिका उन तकनीकी अधिकारियों और इंजीनियरों की नजर आती है, जिन्होंने दफ्तर के बंद कमरों में बैठकर 'वर्चुअल पार्क' की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी। यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर किस आधार पर मूल्यांकन की फाइलें दौड़ाई गईं और किसने उस बंजर जमीन पर हरियाली देखकर हस्ताक्षर कर दिए? क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों को जमीन पर फैला सन्नाटा और कटीली झाड़ियाँ दिखाई नहीं दीं, या फिर 'कमीशन' के खेल ने उनकी आँखों पर भ्रष्टाचार की पट्टी बांध दी थी? यह साफ है कि यह घोटाला केवल एक सचिव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मूल्यांकन करने वाले से लेकर भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने वाले हर हाथ की अपनी हिस्सेदारी नजर आती है।

एक नजर में

समीक्षा बैठक 24 बिंदुओं पर हुई चर्चा

अनूपपुर, नवभारत, 14 फरवरी। डूमर कछार नगर परिषद में शासन द्वारा संचालित नागरिक मूलभूत सुविधाओं को आम जनता तक बेहतर ढंग से पहुँचाने के उद्देश्य से साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन शनिवार, 14 फरवरी को परिषद सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉ. सुनील कुमार चौरसिया अध्यक्ष एवं जिला योजना समिति सदस्य ने की। इस अवसर पर पार्षदगण बिजेंद्र देवांगन, सरिता यादव, रवि सिंह, जीतेंद्र चौहान, पार्वती सिंह गोंड़, राकेश दिवान एवं पार्षद प्रतिनिधि योगेश पालीवाल सहित नगर परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में नगर विकास से जुड़े 24 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, प्रधानमंत्री एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति तथा नागरिक समस्याओं के निराकरण जैसे विषय शामिल रहे।

विजया एकादशी में जगदीश बस्ती से निकली प्रभात फेरी

नवभारत,जबलपुर। फाल्गुन् मास कृष्ण पक्ष शुक्रवार को विजया एकादशी पर्व पर विवेक अग्रवालजी के निवास पी एन तिवारी का बाड़ा महादेव मंदिर पढ़ाव जगदीश बस्ती से प्रात:बेला में प्रभात फेरी निकाली गई। इस अवसर पर गोपाल कोरी, अमित विश्नोई,देवेन्द्र नेमा,अनिल सुहाने,विशाल पड्या, मनोज गुलवानी, सुरेश् शुक्ला, अवधेश खरे,वीरेंद्र नामदेव, मातृ शक्ति रेखा ठाकुर, रंजीता केसरी,मंजू कोष्टा,रश्मि शर्मा, अर्चना पटेल,संगीता केसरवानी, सुषमा गोवस्वामी, भावना अग्रवाल, तारा सेन,भानु रैकवार आदि बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित रहे।

आईआईआईटीडीएम में डिज़ाइन कार्यशाला का दूसरा दिन

नवभारत,जबलपुर। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिज़ाइन एवं विनिर्माण संस्थान (आईआईआईटीडीएम) में आयोजित 10वीं अंतरराष्ट्रीय डिज़ाइन कार्यशाला 'डिज़ाइन कार्यशाला 10.0' के दूसरे दिन उद्योग-केंद्रित तकनीकी सत्रों, विशेषज्ञ संवाद और छात्र गतिविधियों ने विशेष आकर्षण बिखेरा। कार्यशाला का मुख्य विषय 'उद्योग 5.0 में सहजीवी कृत्रिम बुद्धिमत्ता' रहा। दिन की शुरुआत आरईसी लिमिटेड के अधिकारी (अभियंत्रण) एर. नीरज सोनी के विशेषज्ञ व्याख्यान से हुई। उन्होंने विद्युत वितरण प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, बड़े विद्युत ढाँचों में दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने तथा निर्णय-निर्माण को सुदृढ़ करने के व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किए। इसके बाद लिंक्डइन के वरिष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान अभियंता एर. हारून अंसारी ने औद्योगिक निर्णय-निर्माण में विश्वसनीय विशाल भाषा मॉडल (एलएलएम) की भूमिका पर प्रकाश डाला। दोपहर सत्र में ईपैम सिस्टम्स के वरिष्ठ निदेशक एर. संतोष कुलकर्णी ने सहजीवी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा समझाते हुए विनिर्माण और खुदरा क्षेत्रों में मानव-एआई सहयोग के लाभ बताए। अंतिम तकनीकी सत्र में ईवाई, कोलकाता के वरिष्ठ प्रबंधक (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) एर. सतीश अग्रवाल ने एजेंटिक तंत्र और संदर्भ-संवेदी एआई डिज़ाइन विषय पर व्याख्यान दिया। दिन का मुख्य आकर्षण 'सामाजिक हित के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अभियंत्रण' विषय पर छात्र डिज़ाइन प्रदर्शनी रही। चयनित छात्र टीमों ने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, हरित एवं सतत प्रणालियाँ, स्मार्ट अवसंरचना, ऊर्जा समाधान, रोबोटिकी और सहायक उपकरणों से जुड़े नवाचार प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी ने छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप देने का मंच प्रदान किया।

21 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बड़ा आंदोलन

12 फरवरी से प्रदेशव्यापी हड़ताल की चेतावनी

अनूपपुर, नवभारत, 14 फरवरी। अनूपपुर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन (एटक) ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। यूनियन ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए साफ कर दिया है कि यदि मांगे नहीं मानी गईं तो 12 फरवरी से आंदोलन और तेज किया जाएगा।

यूनियन की प्रमुख मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।

इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को 35,000 और सहायिकाओं को 30,000 प्रतिमाह वेतन देने की मांग भी रखी गई है। संगठन ने मांग की है कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 1 करोड़ का बीमा, आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति तथा ग्रेच्युटी का तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यूनियन ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश का भी हवाला दिया।

यूनियन ने सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने तथा सेवानिवृत्ति के बाद 20,000 मासिक पेंशन देने की मांग रखी है। इसके अलावा हर पांच वर्ष में पदोन्नति, मिनी आंगनवाड़ी का मुख्य केंद्र में विलय और 40 दिन का वार्षिक अवकाश भी शामिल है। पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर यूनियन ने कहा कि नेटवर्क और तकनीकी समस्याओं से काम बाधित हो रहा है। मांग की गई है कि डेटा एंट्री के लिए 2,000 अतिरिक्त भत्ता दिया जाए और ऐप को हिंदी में संचालित किया जाए। यूनियन ने आईसीडीएस के निजीकरण पर रोक, फेस कैप्चर व आधार आधारित प्रणाली में सुधार तथा टेक होम राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की मांग भी रखी है। साथ ही 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, पोषण और देखभाल व्यवस्था को मजबूत करने की अपील की गई है। यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लेती तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

इस आंदोलन में अंजली श्रीवास्तव (जिला अध्यक्ष), लीला बांधव (जिला महासचिव), जयंती मार्को (जिला सचिव), उर्मिला पाव (कोषाध्यक्ष), निर्मला केवट, देवमाती, आशा साहू, सोम कुमारी, रुखसाना बेगम, रथे बाई, लीला पानका, सुनीता श्रीवास्तव, गीता, सुमित्रा और चंपावती सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

ग्राम पंचायत चुकान में भ्रष्टाचार का मामला सीपीजीआरएएमएस तक पहुंची शिकायत

- जिला पंचायत सीईओ पर संरक्षण देने का आरोप, सीएम हेल्पलाइन बंद कराने के लिए झूठे आश्वासन का आरोप

अनूपपुर, नवभारत, 14 फरवरी। जिला पंचायत की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर ग्राम पंचायत चुकान के निवासी मूलचंद गुप्ता ने भारत सरकार की सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर ग्राम पंचायत में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में जिला पंचायत अनूपपुर के सीईओ पर भ्रष्टाचार में लिप्त सचिव को संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

ग्राम पंचायत में लाखों के गबन का आरोप

शिकायतकर्ता मूलचंद गुप्ता द्वारा 24 जनवरी को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर पंजीयन क्रमांक डीओआरएलडी/ई/2026/0001016 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में बताया गया है कि ग्राम पंचायत चुकान के प्रभारी सचिव श्रवण द्विवेदी द्वारा पहले से पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों जिनका भुगतान तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा पहले ही किया जा चुका था उन्हीं कार्यों की राशि को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर नए वर्क कोड बनाकर शौचालय और पुलिया निर्माण के नाम पर पुन: आहरित कर लिया गया। शिकायत के अनुसार जांच में यह आरोप सही भी पाया गया, इसके बावजूद दोषी सचिव के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

जिला पंचायत सीईओ पर संरक्षण देने का आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जिला पंचायत अनूपपुर की विहित अधिकारी अर्चना कुमारी तथा सीईओ द्वारा भ्रष्ट सचिव श्रवण द्विवेदी को संरक्षण (अभयदान) दिया जा रहा है। पंचायत अधिनियम की धारा 189/92 के तहत न तो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई और न ही कथित गबन की राशि ग्राम पंचायत चुकान के खाते में वापस जमा कराई गई है।

आयोजन | कोतमा विधानसभा के 25 से ज्यादा पंचायतों में मंगल भवन, कोतमा में पालिका बाजार शॉपिंग काम्पलेक्स का किया लोकार्पण

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हो रहे ठोस प्रयास : राज्यमंत्री

अनूपपुर, नवभारत, 14 फरवरी। राज्य सरकार विकास के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा अनूपपुर जिले को अनेक विकासात्मक सौगातें प्रदान की गई हैं, जिससे जिले में निरंतर प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। जिले में नए उद्योगों की स्थापना की जा रही है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। शनिवार को मध्य प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल कोतमा में पालिका बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं।

राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस एवं प्रभावी प्रयास कर रही है। जरूरतमंद मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है तथा सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय खोले जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जहां विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ संस्कारयुक्त वातावरण भी प्रदान किया जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना , प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त होकर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर उन्हें जनप्रतिनिधित्व का अवसर दिया जा रहा है, जिससे समाज के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी होगी।

राज्य मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जिले के 125 ग्रामों में लगभग 46 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने हेतु कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इससे किसानों को समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा वे विविध फसलों का उत्पादन कर अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को नि:शुल्क सौर पंप उपलब्ध कराने की योजना भी संचालित की जा रही है, जिससे प्रत्येक खेत तक जल उपलब्ध कराया जा सके। इससे किसान अपनी उपज को बाजार में विक्रय कर सकेंगे, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया प्रोत्साहन प्राप्त होगा।